

बैंक, अस्पतालों को राहत, रेस्टोरेंट, क्लब, ब्यूटीपार्लर की आफत

आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि चलाने के मामले में सरकार तैयार कर रही मसौदा

सरकार सप्रीम कोर्ट में रखेगी पक्ष

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद ही मसौदे को कोर्ट में रखा जाएगा. वहीं व्यापारियों का तर्क है कि यदि सख्ती की गई तो राजधानी में एक लाख प्रतिष्ठानों को बंद करने की नौबत आ सकती है. यदि ऐसा हुआ तो 5 लाख लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा.

कन्हैया लोधी

भोपाल, 19 अगस्त. राजधानी भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में कामर्शियल गतिविधियां संचालित होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एक तरफ जहां नगर निगम नोटिस देने की कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में दुविधा में फंसी राज्य सरकार भी राह निकालने में जुटी है, जो कि रहवासी और व्यापारी दोनों के लिए ही स्वीकार्य हो.

नगरीय विकास एवं आवास

नगरीय विकास च्च

आवास विभाग

मध्यप्रदेश

विभाग एक नए फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है, जिसके तहत आवासीय क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को अलग-अलग वर्गों में विभाजित

राज्य सरकार जो मसौदा तैयार कर रही है, उसे 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश किया जा सकता है. सरकार अब तक की कार्यवाही से भी सुप्रीम कोर्ट को अवगत

कराएगी. दरअसल सरकार की दुविधा ये है कि एक तरफ तो रहवासी हैं, जिनका सुकून बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों ने छीन लिया है, वहीं व्यापारी भी हैं, जो बड़ी दुकानें या फिर दूसरी तरह की अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, स्वयं के साथ ही दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं. यदि आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया तो फिर हजारों लोगों के सड़क पर आ जाने का अंदेशा भी है. वे अब आंदोलन की राह भी पकड़ सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार या नगर निगम ने व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्ती नहीं दिखाई और सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं के मुताबिक कार्यवाही नहीं की तो कोर्ट की अवमानना तो होगी ही, रहवासियों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचेगी. मौजूदा हालातों में सरकार अब बीच की रास्ता निकालने की जुगत में है, जिससे कि कोर्ट भी उनकी बातों से संतुष्ट हो सके.

सरकार जो गोपनीय मसौदा तैयार कर रही है, उसके मुताबिक आवासीय क्षेत्रों में चल रही कामर्शियल गतिविधियों को कम से कम 4 वर्गों में विभाजित किया जाएगा. अलग – अलग वर्ग में अलग- अलग श्रेणी की व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल किया जाएगा. एक श्रेणी की व्यावसायिक गतिविधियों को पहले की तरह ही निरंतर जारी रखने की अनुमति दिए जाने की पैरवी की जा सकती है, इनमें बैंक, नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल सहित अन्य वित्तीय संस्थान और एटीएम जैसी सुविधाएं शामिल हैं. दूसरी गतिविधियों को सशर्त अनुमति मिल सकती है, तीसरी श्रेणी की गतिविधियों को शिफ्ट करने के लिए सरकार कुछ समय का रियायत दे सकती है, वहीं चौथी श्रेणी की गतिविधियां में ऐसे संस्थानों को शामिल जाएगा, जो कि विलासिता से जुड़े होंगे. जैसे ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी प्रोडक्ट की दुकानें, क्लब, जिम, रेस्टोरेंट, होटल आदि शामिल हैं. दूसरे और तीसरी श्रेणी में किस तरह की दुकानों और गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, इसे लेकर विभाग में मंथन का दौर लगातार जारी है. ये मसौदा इसी सप्ताह तैयार होने की संभावना जताई जा रही है.

एक नजर में

राजीव जयंती पर कांग्रेस आयोजित करेगी कार्यक्रम

भोपाल. पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वामी राजीव गांधी की 82वीं जयंती के अवसर पर भोपाल शहर जिला कांग्रेस कमेटी और भोपाल जिला कांग्रेस सेवादल द्वारा 20 अगस्त को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह 9.30 बजे सुभाष स्कूल स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से सद्भावना मार्च के साथ होगी. मार्च बिटुन मार्केट चौराहा स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर पहुंचेगा. यहां सुबह 10.30 बजे प्रार्थना सभा और पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसके बाद सुबह 11 बजे शिवाजी नगर स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में राजीव गांधी के चित्र पर कांग्रेस कार्यकर्ता पुष्पांजलि अर्पित करेंगे.

10 वर्ष का बेटा बताएगा पिता की करतूत

मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए बयान

गुरस्से में मायके वालों ने नहीं लिया शव

अनीता और माही के शवों का पोस्टमार्टम कराया . इसके बाद पुलिस अनीता का शव उसके मायके पक्ष को सौंपने वाली थी, लेकिन परिजन ने आरोपी सुनील के प्रति नाराजगी जताते हुए उसे फांसी देने की मांग की और शव लेने से इनकार कर दिया . बाद में दोनों शव सुनील के माता-पिता को सौंपे . उन्होंने अनीता और माही का अंतिम संस्कार किया .

से उसकी वहन माही का शव बाहर निकाला था. वारदात में बालक की मां अनीता चौहान की भी हत्या की गई थी. पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के दौरान आरोपी अपने किए पर पछतावा जताता रहा. पुलिस के मुताबिक वह बार-बार कह रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब वह भी खत्म हो जाएगा. अब पुलिस की जांच में बालक के बयान के साथ आरोपी से पूछताछ को भी अहम माना जा रहा है. पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर वारदात का क्रम समझने के लिए सीन रीक्रेट करा सकती है. इसके बाद रिमांड पूरा होने पर उसे जेल भेजा जाएगा.

विंध्य, बुंदेलखंड में झमाझम के आसार

08 इंच बारिश की संभावना

भोपाल, 19 अगस्त. मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. बुधवार को टीकमगढ़, पन्ना और नरसिंहपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है. वहीं रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, मंडला, शहडोल, सीधी, मऊगंज, रीवा, सतना और छतरपुर में भारी बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के ऊपर बना अवदाब

अब पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है. इसका सबसे ज्यादा असर बुधवार को विंध्य, बुंदेलखंड और महाकौशल में रहने की संभावना है. 20 से 24 अगस्त के बीच बारिश का दायरा धीरे-धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक बढ़ सकता है. लगातार बारिश के बीच

जबलपुर के बरगी बांध के 9 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है. इसके चलते निचले इलाकों में सतकंता बढ़ाई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के अगले चार दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में सक्रिय रहने की संभावना है.

40 जिलों में अब भी बारिश की कमी

प्रदेश में अब तक 573.1 मिलीमीटर यानी 22.6 इंच बारिश दर्ज हुई है, जबकि सामान्य आंकड़ा 651.4 मिलीमीटर यानी 25.6 इंच है. इस तरह प्रदेश में अभी करीब 3 इंच और 12 प्रतिशत बारिश की कमी है. पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से 16 प्रतिशत और पश्चिमी हिस्से में 9 प्रतिशत कम बारिश हुई है. हालांकि अगले कुछ दिनों में तेज बारिश होने पर यह कमी काफी हद तक दूर हो सकती है. लगभग 40 जिलों में अब भी सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है.

पीडीटीसी की वेबसाइट शुरू, सेवाएं ऑनलाइन

भोपाल. मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट शुरू कर डिजिटल सेवाओं की दिशा में कदम बढ़ाया है. वेबसाइट के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संस्थान की अधीसंरचना, छात्रावास सुविधाओं और अन्य जरूरी जानकारीयों ऑनलाइन उपलब्ध होंगी. पीडीटीसी के डायरेक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वेबसाइट पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है. विषय विशेषज्ञ और इच्छुक संकाय सदस्य फ्रैक्टेरी रजिस्ट्रेशन तथा एम्प्लॉयमेंट के लिए अपनी जानकारी भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.

भोपाल, 19 अगस्त . यात्रियों की सुविधा और लंबी दूरी की रेल कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए भोपाल मंडल को दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात मिली है. प्रयागराज-लोकमान्य तिलक और सुबेदारगंज-लोकमान्य तिलक के बीच संचालित हो रही स्पेशल ट्रेनों को अब नियमित अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलाया जाएगा. दोनों ट्रेनों का ठहराव इटारसी स्टेशन पर रहेगा. प्रयागराज-लोकमान्य तिलक अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 21 अगस्त से प्रत्येक शुक्रवार को प्रयागराज से होगा.

भोपाल, 19 अगस्त. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में बच्चों के कुपोषण की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सात पोषण आहार संयंत्र बंद हैं और नई व्यवस्था के लिए अभी तक नए टेंडर जारी नहीं किए गए हैं.

पटवारी ने दावा किया कि एनएफएचएस-5 की तुलना में स्थिति और खराब हुई है. कम वजन की दर 33 से बढ़कर 39.7 प्रतिशत तथा वेंस्टिंग 18.9 से बढ़कर 23.8 प्रतिशत हो गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में कम वजन वाले बच्चों की दर करीब 42 प्रतिशत बताई गई है. उन्होंने विधानसभा में 2025 में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में करीब 1.36 लाख बच्चे कुपोषित थे, जिनमें 29,830 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित थे.

पटवारी ने कहा कि प्रदेश के करीब 97 हजार आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों तथा गर्भवती और धात्री महिलाओं को वर्ष में 300 दिन पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाना है. इसके बावजूद जुलाई तक करीब 170 दिनों का ही पोषण आहार उपलब्ध हो पाया है. इससे लगभग 130 दिनों की कमी सामने आती है. उन्होंने एनएफएचएस-6 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम वजन की

दर मध्यप्रदेश में 39.7 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 31.8 प्रतिशत है. इसी तरह वेंस्टिंग 23.8 प्रतिशत और स्टैंटिंग 31.4 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये क्रमशः 19 और 29.3 प्रतिशत हैं. पटवारी ने कुपोषित बच्चे के लिए प्रतिदिन आठ रुपये और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे के लिए 12 रुपये के प्रावधान पर सवाल उठाते हुए कहा कि गौशालाओं में पशु आहार के लिए प्रतिदिन 40 रुपये का प्रावधान किया जा रहा है.

अनुसंधान केवल दरस्तावेज तक सीमित नहीं रहें

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 19 अगस्त. लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि नवाचार तभी सार्थक है, जब वह प्रयोगशाला से निकलकर वास्तविक निर्माण स्थल तक पहुंचे और मैदानी स्तर पर प्रमाणित परिणाम दे. नवीन तकनीकों को पहले पायलट परियोजनाओं एवं परीक्षण खंडों में परखा जाए तथा खंडों परीक्षण मिलने के बाद उन्हें व्यापक स्तर पर अपनाया जाए. वैज्ञानिक अनुसंधान केवल दरस्तावेजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका सीधा लाभ अधीसंरचना

परियोजनाओं और आमजन तक पहुंचे. मंत्री सिंह बुधवार को सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की प्लॉटिनम जुबली के अवसर पर सीएसआईआर-एएमपीआरआई, भोपाल में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे. कार्यशाला का विषय सतत अधीसंरचना के लिए नवोन्मेषी सामग्री एवं उन्नत कंपोजिट था. इसका संयुक्त आयोजन सीएसआईआर-सीआरआरआई, नई दिल्ली और सीएसआईआर-एएमपीआरआई, भोपाल द्वारा किया गया.

18 साल से फरार इनामी वारंटी को किया गिरफ्तार भिण्ड. भिण्ड देहात थाना पुलिस ने आर्मस् एक्ट के मामले में 18 साल से फरार चल रहे 10 हजार रुपये के इनामी स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी थाने से करीब नौ किलोमीटर दूर अपने ही घर में रह रहा था. पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया. बिजपुरी निवासी प्रीतम भदौरिया को खिलाफ वर्ष 2000 में अपराध क्रमांक 177/2000 दर्ज किया गया था. उसके खिलाफ अवैध हथियार रखने के आरोप में धारा 25 और 27 आर्मस् एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था.

बांधों में जलभराव की लगातार मॉनिटरिंग करें निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए सतर्कता और सुरक्षा के निर्देश भोपाल, 19 अगस्त. जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्रदेश के सभी बांधों, जलाशयों और अन्य जल संरचनाओं में जलभराव की स्थिति की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जलभराव और जलद्वारों के संचालन की जानकारी प्रतिदिन राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाए. बारिश के दौरान विभागीय अमला पूरी तरह सतर्क रहे और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो. मंत्री सिलावट ने बुधवार को मुख्य अभियंता कार्यालय स्थित

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने बांधों में जलभराव, जलद्वारों के संचालन और सुरक्षा उपायों की जानकारी ली. उन्होंने बाढ़ नियंत्रण कक्ष को चौबीसों घंटे जिलों से संपर्क बनाए रखने और स्थिति की निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए. मुख्य अभियंता आरएन मोघान ने बताया कि मानसून सीजन में अब तक 583.40 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो दीर्घावधि औसत से 12 प्रतिशत कम है. पूर्वी मध्यप्रदेश में 14 और पश्चिम हिस्से में करीब 10 प्रतिशत कम बारिश हुई है. विभाग के 54 अति महत्वपूर्ण बांधों में वर्तमान में औसतन 64 प्रतिशत जलभराव है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 74 प्रतिशत था.

कि मानसून सीजन में अब तक 583.40 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो दीर्घावधि औसत से 12 प्रतिशत कम है. पूर्वी मध्यप्रदेश में 14 और पश्चिम हिस्से में करीब 10 प्रतिशत कम बारिश हुई है. विभाग के 54 अति महत्वपूर्ण बांधों में वर्तमान में औसतन 64 प्रतिशत जलभराव है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 74 प्रतिशत था.

रणनीति

संगठन को और मजबूत बनाने के साथ ही जनसंवाद पर रहेगा जोर

2028 की तैयारी में जुटी कांग्रेस

आशीष कुलं

भोपाल, 19 अगस्त. मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज करते हुए संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को ब्रशिक्षित करने और जनता से लगातार संवाद बढ़ाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. यह जानकारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री डॉ. संजय कामले ने दी.

नवभारत से विशेष बातचीत में डॉ. कामले ने कहा कि इसे केवल समय से पहले शुरू किया गया चुनावी अभियान नहीं माना जाना चाहिए. पार्टी का उद्देश्य चुनाव

कार्यक्रम घोषित होने से काफी पहले संगठन और समाज के बीच निरंतर एवं मजबूत संबंध स्थापित करना है. उन्होंने कहा कि संगठनात्मक पुनर्गठन और प्रशिक्षण पूरा होने के

बाद अब नई जिम्मेदारी पदाधिकारियों की है कि वे अपनी भूमिकाओं को नियमित राजनीतिक गतिविधियों और जनसंपर्क में बदलें. केवल संगठन खड़ा करना चुनावी सफलता की गारंटी नहीं हो सकता. डॉ. कामले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित मध्य प्रदेश कार्यक्रमों को भी पार्टी की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया. जबलपुर में जैन-जी के साथ संवाद और उज्जैन में दो संभागों के कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक के माध्यम से पार्टी युवा पीढ़ी से जुड़ने और जमीनी संगठन की तैयारियों का आकलन

करने का प्रयास करेगी. उन्होंने कहा कि 2028 का युवा मतदाता 2023 के मतदाता से अलग अपेक्षाएं रखेगा. रोजगार, शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीक और भविष्य के अवसर जैसे मुद्दों पर युवाओं की बात सुना जरूरी है. राजनीतिक दलों

को पारंपरिक भाषणों से आगे बढ़कर उनकी बदलती आकांक्षाओं और चिंताओं को समझना होगा. उज्जैन बैठक के संबंध में उन्होंने कहा कि इससे नए सिरे से मजबूत किए गए संगठन की जमीनी तैयारियों की समीक्षा होगी.